

अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ
एवं अवधारणाएं

**Most Important Terms and Concepts
Related to Economy**

By – नितिन गुप्ता

Hello Friend , I am नितिन गुप्ता From – Nitin-Gupta.com

दोस्तो , आज की PDF में हम आपको अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ उपलब्ध कराने जा रहे हैं जिनमें से बहुत से Question आपके Exams में आ सकते हैं ! आप इसे अच्छे से पढ़िये और याद कर लीजिये !

Most Important Terms and Concepts Related to Economy

अप्रवासी भारतीय

अप्रवासी भारतीय वे भारतीय हैं जो सामान्यतया भारत में निवास नहीं करते अपितु दूसरे देश में निवास करते हैं तथा उनके पास भारतीय नागरिकता व भारतीय पासपोर्ट होता है।

अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता (Non-Resident (external) Rupee Accounts)

अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता [Non-Resident (external) Rupee Accounts] प्रमुख व्यापारिक बैंकों में अनिवासी भारतीयों के नाम से खोले जा सकते हैं। यह खाते भारतीय रुपयों में खोले जा सकते हैं। खातों का मूल धन तथा उस पर अर्जित ब्याज को बिना किसी कठिनाई के जमाकर्ता को उसके देश वापस कर दिया जाता है, किन्तु रुपयों को विदेशी मुद्रा में उस दर से परिवर्तित किया जाता है, जो कि धन भेजने की तिथि को लागू होती है। ऐसे खाते NRIs तथा भारतीय मूल के विदेशियों द्वारा ही खोले जा सकते हैं।

आउट सोर्सिंग (Out Sourcing)

”आउट सोर्सिंग” का अभिप्राय है किसी कंपनी या फर्म द्वारा किसी कार्य को कंपनी या फर्म से बाहर संपन्न करवाना। दूसरे शब्दों में, विकसित देशों की कंपनियां विकासशील देशों में श्रम सस्ता होने के कारण अपने उत्पादों के विभिन्न निर्माण चरणों को वहां पूर्ण कराती हैं। यही कारण है कि अमेरिकी कांग्रेस के उच्च सदन सीनेट द्वारा अमेरिकन कंपनियों द्वारा की जाने वाली ”आउट सोर्सिंग” पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक संघीय कानून बनाने हेतु विधेयक पारित किया गया है। ये कंपनियां अपनी लागत कम करने के लिए भारत सहित अन्य कंपनियां अपनी लागत कम करने के लिए भारत सहित अन्य देशों से आउट सोर्सिंग कराती हैं।

औसत लागत (Average Cost)

किसी वस्तु के उत्पादन में लगी प्रति इकाई लागत ”औसत लागत” (Average Cost) कहलाती है।

औसत आगम (Average Revenue)

किसी फर्म को प्राप्त होने वाली प्रति इकाई आगम "औसत आगम" (Average Revenue) कहलाता है। कुल आगम को उत्पादन या कुल विक्रय की गई वस्तु की इकाइयों की संख्या से भाग देने पर "औसत आगम" प्राप्त होता है।

अनवीनीकरण योग्य संसाधन (Non-renewable Resources)

अनवीनीकरण योग्य संसाधन (Non-renewable Resources) उन्हें कहा जाता है जिनको सरलतापूर्वक नवीकृत नहीं किया जा सकता। यद्यपि ये संख्या में सीमित हैं, तथापि इनके विशाल भण्डार हैं। जैसे – जीवाश्म तेलों के भण्डार तथा खनिज संसाधन।

अहस्तक्षेप नीति (Laissez Faire)

अहस्तक्षेप नीति (Laissez Faire) एक फ्रांसीसी मुहावरे (हमें अकेला छोड़ दो) की पुष्टि करती है। यह नीति इस बात का द्योतक है कि सरकार को आर्थिक कार्यालयों पर कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए तथा निर्णयों को बाजार पर छोड़ देना चाहिए।

अंतः प्रवासन और बाह्य प्रवासन (In-migration and Out-Migration)

किसी स्थान पर शीघ्र वापिस आने की इच्छा के साथ जाने को अंतःप्रवासन (In-migration) कहते हैं, जबकि शीघ्र ही वापिस न आने की इच्छा से किसी स्थान पर जाने को बाह्य प्रवासन (Out-Migration) कहते हैं। जब यह आवागमन दो देशों के बीच होता है, तब यह प्राप्त करने वाले देश के लिए उत्प्रवास होता है।

आयु विशेष जनन क्षमता (Age Specific Fertility Rate)

किसी दिए वर्ष में, एक विशेष वर्ग में महिलाओं द्वारा दिए गए जन्मों की संख्या को उस आयु वर्ग में आने वाले महिलाओं की संख्या से विभाजित करके जब 1000 से गुणा किया जाता है, तो इसे उस विशेष वर्ष में उस आयु वर्ग की "आयु विशेष जनन क्षमता" (Age Specific Fertility Rate) कहते हैं।

अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone EEZ)

किसी देश में "अनन्य आर्थिक क्षेत्र" (EEZ) से अभिप्राय उसकी समुद्री सीमा से समुद्री तट का वह क्षेत्रफल है जिसके सभी संसाधनों पर उस देश का एकाधिकार होता है तथा इस क्षेत्र के भीतर वह देश उन संसाधनों के दोहन करने हेतु स्वतंत्र होता है। भारत के समुद्री तट से 200 नॉटिकल मील दूरी तक विस्तृत 20.2 लाख वर्ग किमी का समुद्री क्षेत्र भारत का EEZ है।

आर्थिक सहायता और आर्थिक प्रति-सहायता (Subsidisation and Cross-Subsidisation)

जब सामान्य राजस्व द्वारा वसूली के लागत से कम होने के कारण हुई हानि को पूर्ण किया जाता है, तो इसे "आर्थिक सहायता" (Subsidisation) के नाम से जाना जाता है। जब एक उत्पाद के मूल्य को किसी अन्य उत्पाद कल्प से कम करने के लिए बढ़ाया जाए तो इसे "आर्थिक प्रति सहायता" के (Cross-Subsidisation) के नाम से जाना जाता है।

आदेश पत्र

वैदेशिक व्यापार में आयातकर्ता निर्यातकर्ता को निर्दिष्ट माल भेजने के लिए जो पत्र प्रेषित करता है वह आदेश पत्र या "इन्डेन्ट" कहलाता है।

अवमूल्यन (Devaluation)

किसी अन्य मुद्रा की तुलना में जब कोई देश अपनी मुद्रा का अधिकृत मूल्य कम कर दे तो उसे अवमूल्यन (Devaluation) कहते हैं। उदाहरण के लिए, माना कि डॉलर का भारत में अधिकृत मूल्य 55 रुपये था तथा अचानक भारतीय रिजर्व बैंक इसे 65 रुपये कर दे तो इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में सस्ता अथवा डॉलर भारतीय रुपये के मुकाबले महंगा हो गया। मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव यह होता है कि निर्यातों को प्रोत्साहन तथा आयात हतोत्साहित होता है।

आर्बिट्रेज (Arbitrage)

आर्बिट्रेज (Arbitrage) का अर्थ "कीमतों के अंतर का लाभ उठाना" है। दो या दो से अधिक बाजारों के बीच वस्तुओं, वित्तीय प्रतिभूतियों या विदेशी मुद्राओं की खरीद व बिक्री, जिसका उद्देश्य बाजारों में उद्धृत कीमतों के अंतर का लाभ उठाना होता है। जिस बाजार में कीमत कम है, वहां प्रतिभूति या वस्तु को खरीदने तथा उसी समय ऊँची कीमत वाले बाजार में उसे बेचने का सौदा किया जाता है। उसके परिणाम स्वरूप कम कीमत वाले बाजार में मांग बढ़ेगी तथा अधिक कीमत वाले बाजार में कीमत कम होगी और इससे कीमतों में अंतर कम होगा।

अर्थमिति (Econimetrics)

अर्थशास्त्र में अर्थमिति (Econimetrics) के अंतर्गत आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन गणितीय व सांख्यिकीय तकनीकों की सहायता से किया जाता है।

आकस्मिक निधि (Contingency Fund)

भारतीय संविधान के "अनुच्छेद 116" के अंतर्गत "भारतीय संविधान" संसद द्वारा एक आकस्मिक निधि का प्रावधान करता है। इस निधि (Contingency Fund) से राष्ट्रपति की अनुमति से अग्रिम (Advance) निकाले जा सकते हैं तथा इस निधि का उपयोग आकस्मिक रूप से घटित होने वाली घटनाओं का सामना करने हेतु किया जाता है।

आरक्षित मुद्रा पत्र (Fiduciary Currency)

वह कागजी मुद्रा जिसे बिना सोने अथवा चांदी के रिजर्व रखे चलन में लाया गया हो, आरक्षित मुद्रा पत्र (Fiduciary Currency) कहलाती है।

अल्पाधिकार (Oligopoly)

यदि किसी वस्तु के बाजार में विक्रेताओं की संख्या बहुत कम (किन्तु दो से अधिक) होती है, जिनके मध्य आपस में कोई समझौता संभव हो सकता हो, तो ऐसा बाजार अल्पाधिकार (Oligopoly) कहलाता है। इस प्रकार के बाजार में वस्तु एक सी भी हो सकती है तथा वस्तु में विभेद भी हो सकता है।

अनुसूचित व्यापारिक बैंक (Scheduled Commercial Banks)

ऐसे बैंक जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने अपनी दूसरी अनुसूची में सम्मिलित कर दिया है, उन्हें अनुसूचित व्यापारिक बैंक (Scheduled Commercial Banks) कहा जाता है। कुछ आवश्यक शर्तें पूर्ण करने पर ही रिजर्व बैंक द्वारा किसी बैंक को इस अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि बैंक की चुकता पूंजी तथा आरक्षित पूंजी का योग कम से कम 5 लाख रुपये होना चाहिए तथा बैंक का संचालन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें जमाकर्ता के हित सुरक्षित हों।

अधिकृत पूंजी (Authorised Capital)

पूंजी की उस अधिकतम मात्रा को अधिकृत पूंजी कहते हैं जिस सीमा तक कोई कंपनी अपने शेयर जारी कर सकती है। शेयरों का मूल्य अधिकृत पूंजी (Authorised Capital) के बराबर या कम हो सकता है, किन्तु अधिक कम नहीं हो सकता।

आवश्यकता आधारित मजदूरी (Need based wages)

आवश्यकता आधारित मजदूरी (Need based wages) के अंतर्गत एक मजदूर को उसकी नितांत आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। प्रायः यह मजदूरी सामान्य तौर पर मिलने वाली मजदूरी से अधिक होती है।

ऑनलाईन शॉपिंग (Online Shipping)

”इंटरनेट” के बढ़ते उपयोग ने खरीददारी की एक नई प्रणाली अर्थात् ”ऑन लाइन शॉपिंग” के उपयोग की संभावनाओं को नई ऊंचाई प्रदान की है। इसके माध्यम से अनेक वस्तुओं का क्रय किया जा सकता है। अमेरिका इस खरीददारी प्रणाली का अग्रणी देश है। भारत में भारतीय रेलवे द्वारा प्रारंभ की गई ऑन लाइन टिकटिंग एवं बिक्री सेवाएं इसके ज्वलंत उदाहरण हैं।

आर्थिक संवृद्धि

किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करने से 'सकल राष्ट्रीय उत्पाद' (GNP) में हुई वृद्धि, जिसके परिणामस्वरूप "प्रति व्यक्ति आय" (PCI) में वृद्धि होती है। संक्षेप में, आर्थिक वृद्धि (Economic Growth) का प्रयोजन केवल वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में होने वाली वृद्धि से होता है।

अमूर्त सम्पत्तियां, लाभ एवं लागतें (Intangible Assets, Benefits and Costs)

- **अमूर्त सम्पत्तियां (Intangible Assets)** : ऐसी सम्पत्तियां जिनका मूल्य तो है, किन्तु इन्हें देखना या छूना संभव नहीं है। इनमें फर्म की साख, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि शामिल हैं। इन अभौतिक सम्पत्तियों को बेचना या खरीदना भी प्रायः संभव होता है।
- **अमूर्त लाभ (Intangible Benefits)** : किसी परियोजना या उपक्रम से प्राप्त होने वाले ऐसे लाभ जिन्हें देखना संभव नहीं हो। शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वच्छता अथवा सामाजिक कल्याण के उपक्रमों से प्राप्त लाभों का माप नहीं लिया जा सकता क्योंकि वे अमूर्त या अभौतिक हैं। फिर भी ये लाभ किसी समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **अमूर्त लागतें (Intangible Costs)** : ऐसी लागतें जो अनुभव की जाएं किन्तु अमूर्त हैं। यदि जल का वायु के प्रदूषण से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं और उससे श्रमिकों की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव हों तो इसे अमूर्त लागत कहते हैं।

अनुपार्जित आय (Unearned Income)

अनुपार्जित आय (Unearned Income) से तात्पर्य आय के उस भाग से है जो चालू वर्ष में प्राप्त तो हो गया, किन्तु चालू वर्ष से उसका कोई संबंध नहीं होता।

अधिविकर्ष (Overdraft)

बैंको से जमाकर्ता द्वारा अपनी जमा रकम के अतिरिक्त धन निकालना "अधिविकर्ष" (Overdraft) कहलाता है।

आवर्ती जमा या संचयी जमा खाता (Re-curring Deposit Account Or Cumulative Deposit Account)

आवर्ती जमा या संचयी जमा खाता (Re-curring Deposit Account Or Cumulative Deposit Account) खोलने वाले व्यक्ति को एक निश्चित रकम एक नियत अवधि प्रति मास अपने खाते में जमा करनी होती है। यह एक प्रकार का सावधि खाता है। अतः इस खाते पर दिए जाने वाले ब्याज की दर बजत जमा खातों की तुलना में कुछ अधिक होती है।

आदिष्ट चैक

किसी भी धारक चैक (Bearer Cheque) में से जब "धारक" शब्द को काटकार उस पर आदिष्ट (Order) लिख दिया जाए तो वह चैक "आदिष्ट चैक" बन जाता है। इस चैक के भुगतान से पहले भुगतान लेने वाले सही व्यक्ति की पहचान आवश्यकता होती है।

इम्पोर्ट सब्स्टीट्यूशन

जब किसी वस्तु का आयात करने के बजाय देश में ही उत्पादन किया जाय तो इसे "आयात" प्रेरित स्थापन या "Import Substitution" की नीति कहा जाता है। प्रायः विकासशील देशों की रणनीति कुछ वस्तुओं के आयातों पर भारी कर लगाने या उन्हें निषिद्ध श्रेणी में डालकर देश में उनके उत्पादन में वृद्धि करने की रहती है। यह नीति "निर्यात प्रोत्साहन" की नीति से सर्वथा भिन्न है जिसके अनुसार अनुदानों या प्रत्यक्ष सहायता के माध्यम से निर्यातों में वृद्धि करने का प्रयास करती है।

इण्डस्ट्रियल डेमोक्रेसी (Industrial Democracy)

किसी निगम के प्रबंधन में चुने हुए निदेशकों के अलावा श्रमिकों के प्रतिनिधियों की भी निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी होने पर इसे "प्रजातांत्रिक औद्योगिक" व्यवस्था (Industrial Democracy) कहा जाता है।

इकाई बैंकिंग (Unit Banking)

यदि इस बैंकिंग प्रणाली का कार्य मुख्यतया एक ही कार्यालय तक सीमित रहता है, तथापि एक सीमित क्षेत्र में से कुछ शाखाएं भी खोल लेते हैं। यह प्रणाली अमेरिका में पर्याप्त रूप से लोकप्रिय है।

इनोवेशन्स (Innovations)

किसी मौलिक विचार या खोज को व्यवसाय हेतु करना "नवोत्पाद" (Innovations) कहलाता है। यदि वह नवोत्पाद उत्पादन से संबद्ध है तो इसे प्रक्रिया से जुड़ी खोज कहा जाएगा। यदि वस्तु की डिजाइन या गुणवत्ता में इसके कारण सुधार होता है तो यह उत्पादन संबंधी नवोत्पाद है। प्रायः नवोत्पाद हेतु फर्म को पर्याप्त राशि व्यय करनी होती है अथवा इसके फलीभूत होने में पर्याप्त समय लगता है।

इकोमार्क (Ecomarc)

जनवरी, 1992 से पर्यावरण व वन मंत्रालय, भारत सरकार के भारतीय मानक ब्यूरो के ISI चिन्ह की भांति ही एक "Ecomarc" चिन्ह योजना प्रारंभ की है। मिट्टी के मटके के रूप में इकोमार्क एक प्रतीक चिन्ह है, जो किसी भी ऐसे उत्पाद पर प्रदान किया है जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचता।

इण्डिया ब्राण्ड इक्विटी फण्ड

वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार ने विश्व बाजार में भारतीय उत्पादों की छवि बेहतर बनाने और भारतीय निर्यातों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से "इण्डिया ब्राण्ड इक्विटी फण्ड" 11 जुलाई, 1996 को स्थापित किया। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में "भारत में निर्मित" (Made in India) लेबल का गुणवत्ता, प्रतिद्वंद्वतात्मक रूप तथा विश्वसनीयता को प्रतीक बनाना है। इसके लिए खरीददारों की प्रतिक्रिया के आधार पर वस्तुओं व सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए उत्पादकों को प्रोत्साहित किया जाता है।

ई – इलेक्ट्रानिक तथा कामर्स

व्यापारिक लेनदेन। अभिप्राय यह है कि ई-कामर्स के अंतर्गत विक्रेता और क्रेता बिना कागजों की अदला-बदला किए अथवा बिना एक-दूसरे से मिले "इंटरनेट" के माध्यम से लेन-देन करते हैं। साथ ही, यह व्यापार कम्प्यूटर द्वारा टेलीफोन लाइनों से किया जाता है। इस प्रकार के कारोबार के लिए विश्व भर में कम्प्यूटरों का विशेष नेटवर्क कार्यरत है।

इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर (EFT)

इलेक्ट्रानिक फण्ड ट्रांसफर (EFT) व्यवस्था के अंतर्गत एक शहर के भीतर स्थित तथा विभिन्न शहरों में स्थित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं (एक ही बैंक की विभिन्न शाखाओं तथा विभिन्न बैंकों की शाखाओं) के बीच निधियों का हस्तांतरण इलेक्ट्रानिक तरीके से कम्प्यूटर पर ही हो जाता है।

उदार ऋण (Soft Loan)

ऐसा ऋण जिस पर सामान्य जिस पर सामान्य से काफी कम ब्याज लिया जाता है, इसे उदार ऋण (Soft Loan) कहा जाता है। साथ ही, इसकी अदायगी काफी लम्बी अवधि में की जाती है तथा ब्याज तथा मूलधन की अदायगी कुछ अंतराल के बाद की जाती है। कभी-कभी "अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन" (IDA) द्वारा प्रायः इसी प्रकार के उदार ऋण दिए जाते हैं।

उदार मुद्रा (Soft Currency)

उदार या अपरिवर्तनीय मुद्रा (Soft Currency) उसे कहा जाता है जिसके पक्ष में भुगतान संतुलन हो।

उष्ण मुद्रा (Hot Currency)

वह मुद्रा उष्ण मुद्रा (Hot Currency) कहलाती है, जिसकी "विनिमय दर" गिरने की संभावना हो या गिर रही हो। इस कारण इस मुद्रा को स्वीकार करने में लोग हिचक रखते हैं।

उपार्जित आय (Accrued Income)

ऐसी आय जो चालू वर्ष में अर्जित तो कर ली गई है, किन्तु वर्ष के अंत तक वास्तव में प्राप्त नहीं होती, "उपार्जित आय" (Accrued Income) कहलाती है।

ऋण परिवर्तन (Debt Conversion)

किसी सावर्जनिक ऋण की परिपक्वता पर यदि सरकार उसका वास्तविक भुगतान न करके उसके स्थान पर दूसरे नए ऋण पत्र जारी कर दे तो यह प्रक्रिया "ऋण परिवर्तन" (Debt Conversion) कहलाती है।

ऋण शोधन निधि (Sinking Fund)

नियमित रूप से धनराशि जमा करके तैयार किया गया ऐसा कोष जिससे किसी ऋण की परिपक्वता पर आसानी से भुगतान किया जा सके "ऋण शोधन निधि" (Sinking Fund) कहलाता है।

एक्जिट नीति (Exit Policy)

"एक्जिट नीति" को सरकार ने अपनी स्वीकृति मार्च, 1992 में ही दी थी, किन्तु इसके कार्यान्वयन की घोषणा अभी तक नहीं की गई। इसका उद्देश्य रुग्ण व अकुशल उद्योगों को बंद करने के साथ-साथ औद्योगिक उपक्रमों के फालतू कर्मचारियों को मुक्त करना है, जिससे कि अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक भार कम किया जा सके। औद्योगिक रुग्णता पर विचारार्थ गठित "गोस्वामी समिति" ने भी "एक्जिटनीति" अपनाने की अपेक्षा की थी। साथ ही, विश्व बैंक व "अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष" भी अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु इस नीति को अपनाने पर जोर दे रहे हैं।

एडवांस डिक्लाइन (Advance Decline)

एडवांस डिक्लाइन (Advance Decline) शेयर बाजार की प्रवृत्ति प्रदर्शित करने वाला एक माप है। किसी समयावधि में मूल्य वृद्धि को प्रदर्शित करने वाले शेयरों की संख्या का कुल मूल्य ह्रास वाले शेयरों की संख्या के साथ अनुपात ही "एडवांस डिक्लाइन" कहलाता है।

एमोर्टाइजेशन (Amortization)

किसी परिसंपत्ति को इसके जीवनकाल की समाप्ति पर प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था को "Amortization" कहा जाता है। ऋण के संदर्भ में भुगतान की राशि, ब्याज की दर तथा अदायगी की अवधि पर निर्भर करेगी। परिसंपत्ति के प्रतिस्थापना हेतु वांछनीय राशि ब्याज की राशि, परिसंपत्ति भी आपेक्षित आयु तथा मुद्रास्फीति की संभावित दर पर निर्भर करेगी।

एक्साइज ड्यूटी (Excise-duty)

इसे "उत्पाद शुल्क" (Excise-duty) कहते हैं। यह वह कर है जो देश के भीतर निर्मित वस्तुओं के उत्पादन बिन्दु पर लगाया जाता है।

एस्टेट ड्यूटी (Estate duty)

किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी समाप्ति के हस्तांतरण के समय जो कर उस संपत्ति पर लगाया जाता है, उसे "Estate duty" कहते हैं।

एड-वेलोरम (Ad Valorem)

वस्तुओं पर लगाए गए ऐसे कर जो उनकी मात्रा के आधार पर न अधिरोपित कर, उनके मूल्यानुसार लगाया जाता है, उसे "Ad Valorem" कहा जाता है।

एन्युटी (Annuity)

एक मुश्त निवेश को निश्चित अंतराल के साथ समान किश्तों में भुगतान करना "Annuity" कहलाता है। यदि इस निवेश के साथ ब्याज अदायगी समान किश्तों में इस प्रकार सुनिश्चित की जाती है कि निर्दिष्ट अवधि के अंत तक समूची राशि की अदायगी हो जाए। यह नीति बीमा कंपनी द्वारा भी मृतक व्यक्ति की पत्नी (या पति) अथवा आश्रितों को पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर लागू की जा सकती है।

एफ्लुएंट सोसाइटी :

प्रो. जे. के. गालब्रेथ ने इस शब्द (इसका प्रयोग समाज के उस वर्ग के लिए किया जाता है, जो अति संपन्न हैं तथा अपनी तमाम मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उपरांत भी इनके पास इतनी आय बची रहती है कि ये विभिन्न प्रकार के विलासितापूर्ण उपयोग में व्यय करते हैं) का सर्वप्रथम प्रयोग पश्चिमी यूरोप व अमेरिका के संदर्भ में किया था।

एर्गोनॉमिक्स (Ergonomics)

”Ergonomics” किसी श्रमिक की कार्यक्षमता एवं उसके द्वारा किए जाने वाले वास्तविक कार्य के मध्य संबंध का अध्ययन करने वाला विषय है। इसके अध्ययन का उद्देश्य कार्य क्षमता में वृद्धि करना है।

एकक्रेताधिकार (Monopsony)

बाजार की वह स्थिति जिसमें किसी वस्तु अथवा उत्पादन के साधन को केवल एक ही क्रेता हो, एकक्रेताधिकार (Monopsony) कहलाता है। इस विशिष्ट स्थिति के कारण यह क्रेता मनमानी कीमत पर वस्तु या उस साधन को खरीदना चाहता है। परन्तु, प्रायः यदि वह बहुत कम कीमत लगाता है तो साधन या वस्तु का विक्रेता अत्यन्त कम मात्रा बेचना चाहेगा। जैसे-जैसे क्रेता ऊंची कीमत ”ऑफर” करता है, वैसे-वैसे साधन या वस्तु विक्रेता उसकी आपूर्ति बढ़ाते जाएंगे। यही कारण है कि वस्तु विक्रेता उसकी आपूर्ति बढ़ाते जाएंगे। यही कारण है कि क्रेताधिकारी के लिए साधन या वस्तु का पूर्ति चक्र धनात्मक व ढलानयुक्त होता है।

एकाधिकार (Monopoly)

एकाधिकार (Monopoly) उस बाजार स्थिति को कहते हैं, जिसमें एक वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है तथा वैधानिक अथवा विशाल स्तर के कारण किसी नई फर्म का बाजार में प्रवेश नहीं हो पाता ।

क्लोजिंग स्टॉक (Closing Stock)

वह माल जो व्यापार में वर्ष के अंत में प्रयोग होने अथवा विक्रय होने से बच जाता है, उसे "Closing Stock" कहते हैं।

काउण्टर ट्रेड एवं काउंटर गारंटी (Counter Trade Counter Guarantee)

जब कभी दो देशों के पास व्यापार करने हेतु विदेशी मुद्रा के भण्डार नहीं हों इसके बावजूद ये परस्पर व्यापार करना चाहें तो ऐसा प्रति व्यापार के माध्यम से ही हो सकता है। संक्षेप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तु विनिमय को ही प्रति व्यापार (Counter Trade) कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काउण्टर ट्रेड ऐसी नीति है जिसके अंतर्गत हम उस कंपनी/राष्ट्र से आयात करें जो बदले में हमसे आयात करे। "काउंटर गारंटी" निवेशक के निवेश के संरक्षण के परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा दी जाती है। इससे कोई भी विदेशी कंपनी जिस देश में उद्योग स्थापित कर रही है, एक प्रकार से उसका लाभ सुनिश्चित किया जाता है।

काला बाजार (Black Market)

जमाखोरी द्वारा बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करके वस्तुओं की कीमतें बढ़ाकर अधिक लाभ कमाने को "काला बाजार" (Black Market) कहते हैं।

काला धन

ऐसा धन जिसकी उत्पत्ति अवैधानिक गतिविधियों से हुई हो अथवा वह धन जिस पर कोई कर न चुकाया गया हो, काला धन कहलाता है।

करेन्सी तिजोरियां (Currency Chests)

करेन्सी तिजोरियां (Currency Chests) ऐसे बॉक्स हैं जिनमें धात्विक सिक्कों के साथ-साथ नए या पुनः जारी कर सकने योग्य करेन्सी नोटों का भण्डार रखा जाता है। यह तिजोरियों रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंको, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सरकारी खजानों तथा उप खजानों द्वारा संचालित की जाती है।

क्रेता बाजार (Buyer's Market)

वह बाजार जिसमें वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से कम होती है, "क्रेता बाजार" (Buyer's Market) कहलाता है। इसके फलस्वरूप उपभोक्ता कीमतों को नीचे करने में काफी हद तक सफल हो जाता है।

कॉल मनी (Call Money)

किसी कंपनी द्वारा जब शेयर जारी किए जाते हैं, तो शेयर के मूल्य का एक भाग शेयर आवेदनकर्ता से आवेदनपत्र के साथ ले लिया जाता है तथा बची हुई राशि निश्चित तिथि तक किश्तों में मांगी जाती है, जिसे (Call Money) कहा जाता है।

कोर सेक्टर (Core Sector)

अर्थव्यवस्था के विकास हेतु कुछ आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता (जैसे- सीमेंट, लोहा-इस्पात, पेट्रोलियम, भारी मशीनरी इत्यादि) होती है। इन आधारभूत उद्योगों का विकास करके ही अन्य उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। इन्हें "Core Sector" का उद्योग कहा जाता है।

खुला व्यापार (Free Trade)

बिना किसी सरकारी नियंत्रणों के खुले रूप में वस्तुओं का आयात-निर्यात "खुला व्यापार" (Free Trade) कहलाता है।

खुले बाजार की क्रियाएं (Open Market Operations)

केन्द्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न नीतियों में एक प्रमुख "खुले बाजार की क्रियाएं" (Open Market Operations) हैं। इसके अंतर्गत केन्द्रीय बैंक द्वारा मुद्रा बाजार में किसी भी प्रकार के बिलों अथवा प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय होता है। परन्तु, संकीर्ण अर्थ में इससे अभिप्राय केन्द्रीय बैंक द्वारा केवल सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय होता है।

गरीबी रेखा (Poverty Line)

आय का वह स्तर जो अपर्याप्त उपभोग से व्यक्ति को बचाता है, "गरीबी रेखा" (Poverty Line) कहलाता है। दूसरे शब्दों में, वह न्यूनतम आवश्यक आय जो किसी परिवार के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक होती है, वह गरीबी रेखा की सीमा होती है। इससे कम आय प्राप्त करने वाले परिवार को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है।

गैर-निष्पादनीय परिसंपत्तियाँ (Non-Performing Assets)

गैर-निष्पादनीय परिसंपत्तियाँ (Non-Performing Assets) बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा वितरित वे ऋण हैं जिनके मूलधन एवं उस पर देय ब्याज की वापसी समय से नहीं हो पाती।

गैर-योजना ऋण (Non-Plan Loan)

लघु बचतों द्वारा जमा राशि के बदले में राज्य सरकारों को दिया जाने वाला ऋण "गैर-योजना ऋण" (Non-Plan Loan) कहलाता है। इस प्रकार के ऋण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को उनके नकद घाटे और कार्यशील व्ययों को पूर्ण करने के लिए तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को उनके गैर-योजना पूंजी अंतराल को पूर्ण करने आदि के लिए प्रदान किया जाता है।

गिनी गुणांक (Gini Co-efficient)

आय / सम्पत्ति के वितरण में व्याप्त असमानता का सांख्यिकीय माप "गिनी गुणांक" है। यदि गिनी गुणांक शून्य है तो समाज के सभी व्यक्तियों की आय समान मानी जाएगी। इसके विपरीत यदि गिनी गुणांक का मान 1 है, तो इसका आशय यह है कि एक ही व्यक्ति के पास समस्त आय केन्द्रित है। अन्य शब्दों में गिनी गुणांक शून्य से जितना अधिक है, आय या सम्पत्ति के वितरण में उतनी ही अधिक विषमता मानी जाएगी।

गैर-योजना व्यय (Non-Plan Exenditure)

वह सभी सरकारी खर्चें (जैसे – ब्याज, पेंशन, रक्षा, वैदेशिक संबंधों तथा राज्यों को वैधानिक अंतरण पर होने वाले कुछ खर्चें) जो योजना के अंतर्गत नहीं आते "गैर-योजना व्यय" (Non-Plan Exenditure) के अंतर्गत आते हैं।

गिफिन वस्तुएं (Giffin Goods)

ऐसी वस्तु जिसकी कीमत बढ़ने (कम होने) पर उसकी मांग में भी वृद्धि (कमी) होती है, गिफिन वस्तु कहलाती है। इस वस्तु का उपभोग प्रायः समाज का अत्यन्त निम्न आय वाला वर्ग ही करता है। इसीलिए जब गिफिन वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो अन्य वस्तुओं का उपभोग कम करके उपभोक्ता इसकी मांग बढ़ाता है। इसके विपरीत जब कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता अन्य अर्थात् बेहतर वस्तुओं का उपभोग करने हेतु गिफिन वस्तु का उपयोग कम करना चाहता है। इस प्रकार गिफिन वस्तु का कीमत के साथ धनात्मक संबंध होता है।

गैर-योजना अनुदान (Non-Plan Grants)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत वित्त आयोग की सिफारिश पर विशिष्ट योजनाओं के लिए दिया जाने वाला अनुदान गैर-योजना अनुदान (Non-Plan Grants) कहलाता है।

घिसावट (Depreciation)

किसी सम्पत्ति की अनवरत् उपयोग करने से उसके मूल्य में प्रायः कमी होती जाती है, इस मूल्य ह्रास को "घिसावट" (Depreciation) कहा जाता है। मूल्य का ह्रास सम्पत्ति के प्रारंभिक मूल्य एवं उसके जीवन काल पर निर्भर करता है।

घाटा

बजट या विदेशी सौदों से प्राप्तियों की राशि जब भुगतानों की राशि से कम हो तो इसे क्रमशः बजट घाटा (Budget Deficit) / भुगतान संतुलन की ऋणात्मक स्थिति कहा जाता है। इसी तरह जब आयातों की राशि निर्यातों की राशि से अधिक हो तो इसे व्यापार घाटा माना जाता है।

घाटे की वित्त व्यवस्था (Deficit Financing)

जब कभी बजट घाटे को पाटने हेतु सरकार केन्द्रीय बैंक से ऋण लेती है तो यह "घाटे की वित्त व्यवस्था" (Deficit Financing) कहलाती है।

चालू खाता (Current Account)

यह एक प्रकार की मांग जमा (Demand Deposit) खाता है, जिसे "Current Account" कहा जाता है। किसी देश के विदेश व्यापार(दृश्य) एवं अदृश्य व्यापार की दशा में प्रस्तुत करने वाली, तालिका, जो निर्दिष्ट अवधि में उस देश के भुगतान शेष को दर्शाती है। बैंक जमा खाते का अर्थ है – इन खातों में जमा राशियों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता, अपितु बैंक लेन-देनों की संख्या के आधार पर कुछ सेवा शुल्क खाताधारी से वसूल करता है।

चालू कीमतें (Current Prices)

निर्दिष्ट अवधि में प्रचलित औसत कीमतें "चालू कीमतें" (Current Prices) कहलाती हैं, जैसे कि 2003-04 की औसत कीमतों के आधार पर "सकल घरेलू उत्पाद" का अनुमान करना हो तो इस वर्ष प्रचलित कीमतों के औसत से संबद्ध वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा को गुणा किया जाता है। चालू कीमतों में "मुद्रास्फीति" या संकुचन का प्रभाव दिखाई देता है।

चक्रीय बेरोजगारी (Cyclical Unemployment)

किसी व्यापार चक्र में मंदी काल में सकल मांग का स्तर नीचा होने के कारण परिलक्षित बेरोजगारी को "चक्रीय बेरोजगारी" (Cyclical Unemployment) कहते हैं। यह बेरोजगारी व्यापार चक्र के अगले काल(अर्थात् स्फीति वाले काल) में स्वतः लुप्त हो जाती है। इसका कारण यह है कि उस अवधि में कीमतें, उत्पादन तथा सकल मांग में वृद्धि होती है।

चिट फंड (Chit Fund)

कुछ लोग मिलकर लघु बचतों के सदुपयोग की दिशा में निश्चित नियमों के सदुपयोग की दिशा में निश्चित नियमों के अंतर्गत "चित फंड" (Chit Fund) का निर्माण करते हैं, जिसमें प्रत्येक सदस्य निश्चित राशि देता है और इस राशि को प्रत्येक महीने आवश्यकतानुसार किसी एक सदस्य को प्रदान कर दिया जाता है।

चार्टर पार्टी

”चार्टर पार्टी” निर्यातक एवं जहाजी कंपनी के मध्य इस प्रकार का एक प्रकार का एक अनुबंध है, जिसमें कंपनी किसी निर्दिष्ट जहाज पर निर्यातक के माल के अतिरिक्त किसी अन्य का माल नहीं ले जाती। पूरे जहाज को ठेके पर लेने के लिए जो वचन-पत्र देना होता है, उसे ही चार्टरपार्टी या जहाजी प्रसंविदा प्रपत्र के नाम से पुकारा जाता है।

जीरो नेट एड (Zero Net Aid)

जब किसी देश विशेष की आर्थिक व्यवस्था स्वनिर्भर हो जाती है तथा उसे किसी विदेशी आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं होती, तो वह ”जीरो नेट एड” (Zero Net Aid) कहलाती है।

जीरो बेस बजटिंग (Zero base budgeting)

”शून्य आधार बजट निर्माण” (Zero base budgeting) व्यवस्था के अंतर्गत सरकार या किसी भी संगठन को बजट के सिद्धांतों से प्रारंभ करते हुए संगठन या सरकारी नीतियों के उद्देश्य की व्याख्या करनी चाहिए तथा यह स्पष्ट करना चाहिए कि किस तरह प्रस्तावित बजट उन उद्देश्यों की पूर्ति का माध्यम हो सकेगा। सामान्य प्रचलित व्यवस्था में गत वर्ष के राजस्व, अन्य प्राप्तियों, राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय के अनुमानों का विवरण दिया जाता है। प्रायः गत वर्ष के आय-व्यय की राशियों में नाम मात्र का परिवर्तन करके आगामी वर्ष के प्रस्तावों तथा अनुमानों को निरूपित कर दिया जाता है। शून्य आधारित बजट व्यवस्था की यह विशेषता होती है कि इसमें जनता की आकांक्षाओं, सरकारी नीतियों विगत खर्चों तथा आय, प्रस्तावित खर्चों की वांछनीयता तथा उनकी पूर्ति हेतु बजट में प्रस्तावित करें आदि के बीच सामंजस्य रखा जाता है। भारत में बजट वर्ष 1987-88 से ”शून्य आधारित बजट” लागू करने का निर्णय लिया गया।

जीरो कूपन बॉण्ड (Zero Coupon Bond)

यह ऐसी सरकारी प्रतिभूतियां हैं जिन पर प्रत्यक्ष रूप से कोई ब्याज देय नहीं होता। साथ ही, परिपक्वता पर केवल अंकित मूल्य का ही भुगतान किया जाता है। परन्तु, ऐसे बॉण्डों की ब्रिकी अंकित मूल्य से कम पर ही की जाती है। इस प्रकार इन बॉण्डों के क्रय मूल्य व अंकित मूल्य का अंतर ही सरकार पर ब्याज भार है।

जन्मदर (Birth Rate)

प्रति हजार जनसंख्या के पीछे जितने के पीछे जितने बच्चों का जन्म हुआ, उसे जन्मदर (Birth Rate) कहते हैं।

जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy)

किसी भी देश के लोगों के जीवित रहने की औसत आयु को "जीवन प्रत्याशा" (Life Expectancy) कहा जाता है।

जीवन निर्वाह सूचकांक (Cost of Living Index)

किसी आधार वर्ष के आधार पर बनाया गया वह सूचकांक जो जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है, "जीवन निर्वाह सूचकांक" (Cost of Living Index) कहलाता है। इसी के आधार पर वेतन आदि में संशोधन किया जाता है।

सी. आर. फार्म

विदेशी व्यापार प्रक्रिया के अंतर्गत जी. आर. फार्म रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित वह फार्म है, जिसे निर्यातक द्वारा भरकर रिजर्व बैंक को देना होता है। इससे बैंक को यह जानकारी प्राप्त होती है कि विदेशों में बेचे गए माल से जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी वह भारत में प्रेषित कर दी जाएगी।

तेजडिया व मंदडिया (Bulls and Bears)

यह शब्द स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित हैं। जो व्यक्ति स्टॉक मार्केट की कीमतें बढ़ाना चाहता है, उसे तेजडिया (Bulls) कहते हैं, जबकि जो व्यक्ति कीमतें गिराने की आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वायदा करके बेचता है, वह मंदडिया (Bears) कहलाता है।

तरलता (Liquidity)

किसी सम्पत्ति या वस्तु की नकद मुद्रा में परिवर्तनीयता "तरलता" (Liquidity) कहलाता है। विदेशी मुद्रा, बैंक जमाओं आदि में अत्यधिक तरलता पाई जाती है।

तरल सम्पत्तियां (Liquid Assets)

ऐसी मौद्रिक सम्पत्ति (मुद्रा) जिसे सीधे ही भुगतान हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है, तरल सम्पत्तिया (Liquid Assets) कहलाती हैं।

तरलता की कठिनाई (Liquidity Constraint)

किसी व्यक्ति अथवा फर्म को वांछित ऋण की प्राप्ति न होना "तरलता की कठिनाई" (Liquidity Constraint) कहलाती है।

तरलता अनुपात (Liquidity Ratio)

वित्तीय संस्थाओं विशेषतया बैंकों की कुल देनदारियों में तरल सम्पत्ति का अनुपात "तरलता अनुपात" (Liquidity Ratio) कहलाता है। प्रायः केन्द्रीय बैंक अथवा कानून द्वारा तरलता का एक न्यूनतम अनुपात निर्धारित किया जाता है।

दोहरी गणना (Double Counting)

राष्ट्रीय आय का अनुमान करते समय प्रायः प्रत्येक फर्म द्वारा उत्पादित अन्तिम वस्तु का मूल्य लिया जाता है तथा इसके अन्य फर्मों से खरीदे गए "Inputs" को घटाया नहीं जाता। वस्तुतः ये इनपुट्स उन फर्मों के उत्पादों का मूल्य लेने पर दोहरी गणना (Double Counting) की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

दोहरा करारोपण (Double Taxation)

किसी एक ही आय पर दो राज्यों या दो देशों द्वारा कर लगाया जाना, "दोहरा करारोपण" कहलाता है। ऐसा तब होता है जब किसी कंपनी की सम्पत्ति से एक देश में अर्जित आय पर उस देश में कर लगाया जाता है। परन्तु, यदि वह कम्पनी मूलतः दूसरे देश में स्थित हो और वहां भी पहले देश में अर्जित आय पर करारोपण कर दिया जाए। इस प्रकार एक ही आय पर कंपनी दोहरा कर देती है।

दोहरी अर्थव्यवस्था (Dual Economy)

ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पूंजी गहन तकनीक का उपयोग कुछ क्षेत्रों में होता है और साथ ही उन्हीं क्षेत्रों या अन्य क्षेत्रों में परम्परागत व श्रम गहन तकनीक भी प्रयुक्त होती हो, तो "दोहरी अर्थव्यवस्था" (Dual Economy) कहा जाता है। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र में भारत में उच्च स्तरीय पूंजी गहन तकनीक के साथ बैलों से जुताई या सिंचाई की तकनीक भी प्रयुक्त हो रही है।

द्वैधिकार (Duopoly)

द्वैधिकार (Duopoly) बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के केवल दो उत्पादक या विक्रेता होते हैं।

द्विक्रेताधिकार (Duopsony)

द्विक्रेताधिकार (Duopsony) ऐसे बाजार को कहा जाता है जिसमें किसी वस्तु के दो क्रेता होते हैं।

दृश्य अथवा मूर्त प्रतिभूति (Tangible security)

दृश्य प्रतिभूति (Tangible security) में ऋण की वसूली प्रतिभूति बेचकर की जा सकती है। दृश्य प्रतिभूति में शेयर, डिबेंचर्स, सरकारी प्रतिभूति, माल एवं जीवन बीमा पालिसी आदि को शामिल किया जाता है।

देशी बैंकिंग (Indigenous Banking)

भारत में देशी बैंकिंग (Indigenous Banking) व्यवस्था के अंतर्गत सर्राफ, सेठ साहूकार, महाजन तथा शेटी आदि को सम्मिलित किया जाता है।

धारक ऋण पत्र (Bonds)

ऐसी वित्तीय प्रतिभूतियां जिन पर किसी व्यक्ति या फर्म का नाम अंकित नहीं होता तथा धारक ही इस प्रकार के ऋण पत्र या प्रतिभूति का स्वामी माना जाता है, "धारक ऋण पत्र" (Bonds) कहलाता है।

नकद कटौती (Cash Discount)

नकद कटौती (Cash Discount) उन व्यापारियों को प्रदान की जाती है, जो एक निश्चित तिथि से पूर्व भुगतान नकदी में कर देते हैं।

निचले स्तर से नियोजन (Planning from below)

निचले स्तर से नियोजन (Planning from below) का आशय ऐसे नियोजन से है जिसमें समाज के निर्धन व पिछड़े वर्गों को योजना का सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो।

नकद आरक्षण अनुपात (Cash Reserve Ratio, CRR)

व्यापारिक बैंकों द्वारा अपनी जमाओं व देनदारियों का वह भाग जिसे उन्हें रिजर्व बैंक के पास नकद के रूप में रखना होता है, "नकद आरक्षण अनुपात" (CRR) कहा जाता है। रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 42(1) के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों को यह अनिवार्य है कि वे अपनी जमा राशि के कम से कम 3% के बराबर रकम रिजर्व बैंक के पास नकद रूप में जमा रखें। रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि वह उस अनुपात का बढ़ाकर 15% तक कर सकता है।

निगम कर (Planning from below)

यह एक प्रत्यक्ष कर है, जो कम्पनियों के मुनाफे पर लगाया जाता है, इसे अंग्रेजी में "Corporate Tax" कहते हैं।

निजी क्षेत्र (Private Sector)

अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र को निजी क्षेत्र (Private Sector) कहते हैं, जिसमें आर्थिक संसाधनों पर निजी नियंत्रण होता है तथा निजी लाभ के उद्देश्य से ही इनका उपयोग किया जाता है।

प्लास्टिक मनी (Plastic Money)

विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा अन्य कंपनियों द्वारा जारी किए गए "क्रेडिट कार्ड" को प्लास्टिक मुद्रा" (Plastic Money) कहा जाता है।

प्रशासित मूल्य (Administred Price)

जब किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण बाजार की मांग व पूर्तिकी स्वतंत्र शक्तियों द्वारा न होकर किसी केन्द्रीय शक्ति द्वारा होता है, तो इस प्रकार का मूल्य "प्रशासित मूल्य" (Administred Price) कहलाता है।

परिवर्तनशीलता (Convertibility)

एक विदेशी मुद्रा अथवा अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व कोष की अन्य विदेशी मुद्राओं में परिवर्तनशीलता की स्वतंत्रता "प्रतिवर्तनशीलता" कहलाती है। ऐसी मान्यता है कि यह परिवर्तनशीलता जितनी मुक्त होगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा पूंजी का प्रवाह बढ़ने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।

प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment)

यह इस प्रकार की बेरोजगारी है जिसमें व्यक्तिस्पष्ट रूप से बेरोजगार प्रतीत नहीं होते हैं। वे काम पर तो लगे होते हैं, किन्तु उस काम में उनकी सीमान्त उत्पादकता शून्य होती है। भारत में कृषिक्षेत्र में पर्याप्त प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी (Disguised Unemployment) पाई जाती है।

पेटेंट (Patent)

नए उत्पाद, उत्पादन की नई प्रक्रिया तथा नई तकनीक के आविष्कार को सरकार द्वारा दी गई औपचारिक मान्यता "पेटेंट" कहलाती है। पेटेंट प्राप्त होने पर इसके धारक को एक प्रकार का एकाधिकार प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उस प्रकार की वस्तु का उत्पाद, उस प्रकार की प्रक्रिया तथा तकनीक का उपयोग अन्य कोई फर्म नहीं कर सकती। परन्तु, पेटेंट धारक की निरंकुशता को नियमित करने हेतु प्रायः सरकार पेटेंट का पंजीकरण एक निर्दिष्ट समय के लिए ही करती है, जिसका नवीनीकरण अनिवार्य होता है।

पूर्ति की लोच (Elasticity of Supply)

किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के परिणामस्वरूप उस वस्तु की पूर्ति की गई मात्रा में सापेक्षिक परिवर्तन की दर को पूर्ति की लोच (elasticity of Supply) कहते हैं

प्रारंभिक जमा (Primary Deposits)

प्रारंभिक जमा (Primary Deposits) से तात्पर्य उन जमा राशियों से है, जो नकदी अथवा वास्तविक मुद्रा के रूप में जमाकर्ताओं द्वारा बैंक में जमा की जाती हैं।

प्रतिभूति (Security)

प्रतिभूति एक व्यापक शब्द है। एक अर्थ में प्रतिभूति (Security) शब्द का प्रयोग प्रपत्रों के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियाँ जैसे कि शेयर, डिबेंचर्स व अन्य ऋण पत्रों आदि के लिए किया जाता है। बैंकिंग प्रणाली में ऋणों की जमानत के संदर्भ में भी "प्रतिभूति" शब्द प्रयुक्त होता है। यहां प्रतिभूति से अभिप्राय: उस बीमित हित से होता है, जो ऋण के भुगतान न होने की स्थिति में उत्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में, प्रतिभूति ऋण का बीमा होती है। बैंकों द्वारा ऋण लेने वाले को व्यक्तिगत अथवा दृश्य प्रतिभूति पर ऋण प्रदान किया जाता है।

प्राथमिक प्रतिभूति (Primary Security)

प्राथमिक प्रतिभूति (Primary Security) से अभिप्राय उस प्रतिभूति से होता है, जो ऋण को मुख्यतया सुरक्षित करता है तथा यह प्रतिभूति ऋणी द्वारा प्रदत्त की जाती है।

पूंजी बाजार (Capital Market)

वह बाजार जहां पर उद्यम की दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति होती है, पूंजी बाजार (Capital Market) कहलाता है।

प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income)

जब किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग किया जाता है, तो प्राप्त होने वाली आय प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) कहलाती है।

पेट्रो डॉलर (Petro Dollar)

पेट्रोलियम निर्यातक देशों द्वारा पेट्रोल की ऊँची कीमतों पर बिक्री के द्वारा जो विदेशी मुद्रा (मुख्यतया अमेरिकी डॉलर के रूप में) प्राप्त की जाती है, उसे "Petro Dollar" कहते हैं।

पूंजी बजट (Capital Budget)

पूंजी बजट (Capital Budget) के अंतर्गत पूंजी प्राप्ति और पूंजी भुगतान का विवरण होता है।

पूंजी उत्पाद अनुपात (Capital Output Ratio)

प्रति ईकाई उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा "पूंजी उत्पाद अनुपात" (Capital Output Ratio) कहलाती है।

पोर्टफोलियो (Portfolio)

विभिन्न प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों को जो किसी निवेशकर्ता के पास उपलब्ध रहती है, "Portfolio" कहा जाता है।

प्राकृतिक वृद्धि दर (Rate of Natural Growth)

जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को "प्राकृतिक वृद्धि दर" (Rate of Natural Growth) कहा जाता है।

प्राथमिक घाटा (Primary Deficit)

यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज के भुगतान को घटा दिया जाता है तो प्राप्त होने वाली राशि "प्राथमिक घाटा" (Primary Deficit) कहलाती है।

फ्लोटिंग ऑफ करेंसी (Floating of Currency)

किसी मुद्रा की विनिमय दर को स्वतंत्र छोड़ देना जिससे कि मांग और आपूर्ति की दशाओं के आधार पर वह अपना नया मूल्य तय कर सके, "Floating of Currency" कहलाता है।

फिड्यूसियरी इश्यू (Fiduciary Issue)

बिना रिजर्व रखे कागजी मुद्रा का चलन में ले आना "Fiduciary Issue" कहलाता है।

फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (Foreign Direct Investment, FDI)

किसी देश के व्यक्तियों या संस्थानों द्वारा अन्य देश की फर्मों की संपत्ति पर अधिकार अथवा सीधे उत्पादक संरचनाओं में निवेश करना FDI कहलाता है। इसमें इन संस्थाओं की पूंजी में भागीदारी तथा उन्हें खरीदना भी शामिल है। निवेशकर्ता को निवेशित पूंजी पर अर्जित लाभांश को अपने देश में भिजवाने की पूंजी स्वतंत्रता रहती है।

फैक्टर कास्ट (Factor Cost)

उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त साधनों की लागत को उत्पादन लागत (Factor Cost) कहते हैं।

फैक्टर इंटैनिसटी (Factor Intensity)

वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में प्रयुक्त साधनों का अनुपात अथवा सापेक्ष भाग "Factor Intensity" कहलाता है।

फॉरवर्ड मार्केट (Forward Market)

फॉरवर्ड मार्केट (Forward Market) एक ऐसा बाजार है जिसमें वस्तु, प्रतिभूति या विदेशी मुद्रा को अग्रिम रूप में बेचने या खरीदने का सौदा किया जाता है।

फ्रेंचाइजी (Franchise)

दो या दो से अधिक फर्मों को एक सामान्य व्यवस्था के संचालन हेतु अधिकृत किया जाना "Franchise" कहलाता है।

फ्यूचर मार्केट (Future Markets)

वह बाजार जिसमें वस्तुओं, प्रतिभूतियों अथवा विदेशी मुद्राओं की खरीद हेतु सौदे तो आज की तिथि में किए जाएं, किन्तु इसके समापन हेतु भविष्य की कोई तिथि रखी जाती है, "Future Markets" कहलाता है।

फ्री ट्रेड एरिया

यह एक प्रकार का व्यापार समझौता है, जिसके अंतर्गत सम्बद्ध देशों द्वारा परस्पर व्यापार हेतु सभी प्रकार की पाबंदियां, कर तथा नियंत्रणों को समाप्त कर दिया जाता है।

बजट

सरकार द्वारा निरूपित प्राप्तियों तथा खर्चों का विवरण जिस पर संसद अथवा कार्यपालिका की मुहर लगवाई जाती है "बजट" कहलाता है।

बहुराष्ट्रीय निगम (Multinational Corporation)

एक ऐसी कंपनी जिसके कार्य क्षेत्र का विस्तार एक से अधिक देशों में होता है और जिसका उत्पादन एवं सुविधाएं उस देश से बाहर भी संपन्न होती हैं, जिसमें यह जन्म लेती है, तो ऐसी कंपनी को "बहुराष्ट्रीय निगम" (Multinational Corporation) कहा जाता है।

बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights)

किसी विशिष्ट बौद्धिक पद्धति से विकसित वस्तु, सेवा या तकनीक का स्व-उपयोग करने का अधिकार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसका उपयोग करने पर प्रतिबंध का अधिकार या उचित मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार "बौद्धिक संपदा अधिकार" (IPR) कहलाता है।

बूम (Boom)

अर्थव्यवस्था में "Boom" का स्थिति उस समय प्रत्यक्ष होती है, जब आर्थिक क्रियाओं का तेजी से विस्तार होता है। मांग में वृद्धि को परिणामस्वरूप किसी उद्योग विशेष में भी यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

बफर स्टॉक (Buffer Stock)

आपात स्थिति में किसी वस्तु की कमी को पूर्ण करने के लिए वस्तु का स्टॉक तैयार करना "बफर स्टॉक" (Buffer Stock) कहलाता है।

ब्रिज लोन (Bridge Loan)

कंपनियां प्रायः अपनी पूंजी का विस्तार करने के लिए नए शेयर तथा "डिबेंचर्स" जारी करती रहती हैं। कंपनी को शेयर जारी करके पूंजी जुटाने में 3 माह से भी अधिक समय लगता है। इस कंपनियां बैंकों से अंतरिम अवधि के लिए जो ऋण प्राप्त करती हैं, वह Bridge Loan कहलाता है।

बैड डेब्ट (Bad Debt)

वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव न हो "Bad Debt" कहलाता है।

ब्ल्यू चिप (Blue Chip)

"Blue Chip" शब्द प्रायः उन कम्पनियों के शेयरों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो अत्यन्त सुदृढ़ हैं तथा जिनका प्रबंधन आदि अति कुशल है। ऐसे शेयरों को खरीदने में हानि की संभावना बहुत कम होती है।

बॉण्ड अथवा डिबेंचर (Bond and Debenture)

बॉण्ड एवं डिबेंचर (Bond and Debenture) का अर्थ ऋण पत्रों से होता है, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी संस्थान द्वारा ऋण लेकर जारी किया जाता है।

बैंक दर (Bank Rate)

बैंक दर (Bank Rate) से अभिप्राय उस दर से है, जिस पर केन्द्रीय बैंक सदस्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है अथवा स्वीकार्य प्रतिभूतियों पर ऋण देता है। कुछ देशों में इसे कटौती दर भी कहा जाता है।

भुगतान संतुलन या भुगतान शेष (Balance of Payments)

एक निर्दिष्ट अवधि में किसी देश का शेष विश्व के साथ हुए व्यापार तथा वित्तीय प्रवाहों का वितरण भुगतान शेष (Balance of Payments) कहलाता है। यह दो खण्डों में विभाजित होता है – चालू खाता एवं पूंजी खाता। चालू खाते में दृश्य और अदृश्य मदों के व्यापार का लेखा होता है, जबकि पूंजी खाते में विनियोग एवं अन्य पूंजी प्रवाहों का लेखा होता है।

भूमण्डलीयकरण (Globalization)

भूमण्डलीकरण अथवा वैश्वीकरण का तात्पर्य है – "देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना" दूसरे शब्दों में प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी एवं श्रम के साथ बौद्धिक संपदाओं का निर्बाध आदान-प्रदान ही भूमण्डलीकरण कहलाता है। भूमण्डलीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक देश कुछ बाजारोन्मुखी आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम क्रियान्वित करे, इस हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं व व्यापारिक संस्थाओं द्वारा कुछ निर्देशक सिद्धांत सुझाए गए हैं।

भुगतान शेष का संकट :

भुगतान शेष का संकट एक ऐसी स्थिति होती है, जिसमें किसी देश के विदेशी मुद्राओं के कोष तेजी से तथा लगातार कम हो रहे हों।

भारतीय मानक ब्यूरो :

मानकीकरण, गुणवत्ता प्रमाणन और विवर्णन गतिविधियों के सुव्यवस्थित विकास हेतु 6 जनवरी, 1947 को "भारतीय मानक ब्यूरो" एक पंजीकृत संस्थान के रूप में अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय दिल्ली में है।

मूर्त सम्पत्तियां (Tangible Assets)

मूर्त सम्पत्तियां (Tangible Assets) एक ऐसी सम्पत्तियां होती हैं, जिन्हें देखा, छुआ तथा अनुभव किया जा सकता है। जैसे – भूमि, भवन, मशीनरी, माल, रोकड़, मोटरगाड़ियां आदि। इसके विपरीत "अमूर्त संपत्तियाँ" (Intangible Assets) का भौतिक अस्तित्व नहीं होता किन्तु इनका मूल्य स्वामित्व एवं कब्जे के द्वारा प्रदत्त अधिकारों से प्राप्त (जैसे – ख्याति, पेटेंट, व्यापारिक चिन्ह, कॉपीराइट आदि) किया जाता है।

मध्य पतन व्यापार (Enterport Trade)

पुनरिर्थात हेतु आयात करना मध्य पतन व्यापार (Enterport Trade) कहलाता है।

मानव विकास निर्देशांक (Human Development Index, HDI)

एक राष्ट्र में बुनियादी मानवीय योग्यता की औसत प्राप्ति को मानव विकास निर्देशांक (Human Development Index, HDI) द्वारा मापा जाता है। इसका आकलन संबंधित देश में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा के स्तर तथा वास्तविक आय के आधार पर किया जाता है।

मुद्रा संकुचन (Deflation)

जब बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतें गिर जाती हैं, उत्पादन व व्यापार गिर जाता है तथा बेरोजगारी बढ़ती है, तो वह अवस्था "मुद्रा संकुचन" (Deflation) कहलाती है।

मुद्रास्फीति (Inflation)

सामान्य कीमत स्तर में काफी समय तक वृद्धि होने की प्रवृत्ति को "मुद्रास्फीति" (Inflation) कहा जाता है। इस अवस्था में मुद्रा मूल्य गिर जाता है तथा कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि इससे उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है, किन्तु एक सीमा से अधिक मुद्रास्फीति हानिकारक है।

मुद्रा बाजार या पूंजी बाजार (Money Market)

मुद्रा बाजार (Money Market) के अंतर्गत उन समस्त व्यक्तियों व वित्तीय संस्थाओं को शामिल किया जाता है, जो अल्पकाल के लिए मुद्रा उपलब्ध कराते हैं।

मिंट (Mint)

सरकारी मुद्रा का निर्गम करने वाली संस्था को मिंट (Mint) कहते हैं। इस संस्था के पास सिक्कों या करेंसी नोट के प्रकाशन का सर्वाधिक सुरक्षित रहता है।

मेरिट गुड्स एवं मेरिट सब्सिडीज (Merit Goods and Merit Subsidies)

ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति प्रायः सरकार जनहित के लिए कर सकती है, जैसे जन स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा आदि, वैसी वस्तुएं "मेरिट गुड्स" कहलाती हैं। दूसरी ओर, ऐसा अनुदान जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ाने में सहायक हो, "मेरिट सब्सिडीज" कहलाती है।

मौद्रिक नीति (Monetary Policy)

सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में प्रचलित ब्याज दर तथा मुद्रा (करेंसी एवं साख) पर नियंत्रण रखने वाली नीति "मौद्रिक नीति" (Monetary Policy) कहलाती है।

मौद्रिक प्रणाली (Monetary System)

किसी देश की सरकार द्वारा मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने हेतु अपनाई गई नीतियां तथा तत्संबंधी तौर-तरीके "मौद्रिक प्रणाली" (Monetary System) कहलाती है।

मिश्रित मांग (Composite Demand)

जब कोई वस्तु एक से अधिक उपयोगों में प्रयुक्त की जाती है, तो ऐसी वस्तु की कुल मांग उसकी विविध उपयोगों हेतु मांग का योग होती है। इसे "मिश्रित मांग" (Composite Demand) कहा जाता है।

मुद्रा अस्फीति अथवा विस्फीति (Disinflation)

सामान्य कीमत स्तर में कमी जो प्रायः राष्ट्रीय आय में ह्रास के साथ-साथ चलती है, "मुद्रा अस्फीति" (Disinflation) कहलाती है। जब मौद्रिक अधिकारी मुद्रा स्फीति पर अंकुश लगाने हेतु कोई कार्यवाही करते हैं और उसके फलस्वरूप जब कीमत स्तर में कमी होती है तो इसे अपस्फीति कहा जाता है।

मांग जमा :

मांग जमाओं के अंतर्गत उन समस्त जमा राशियों को सम्मिलित किया जाता है, जो जमाकर्ता द्वारा अपनी इच्छानुसार चाहे जब वापस मांगी जा सकती है। बैंकों के चालू खाते तथा बचत खाते में जमा राशियों इसके अंतर्गत ही आती हैं।

मर्चेन्ट बैंकिंग :

इसके अंतर्गत औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्थानों को विशिष्ट प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

मल्टीपल एक्सचेंज रेट (Multiple Exchange Rates)

ऐसी प्रणाली जिसमें किसी देश की विनिमय दरें किसी अन्य देश की मुद्रा के संबंध में दो या अधिक हो सकती हैं, उसे "Multiple Exchange Rates" कहते हैं।

म्युचुअल फण्ड (Mutual Fund)

एक ऐसी वित्तीय संस्था जिसके पास निवेशकों की राशि रहती है, "Mutual Fund" कहलाती है। भारत की सबसे बड़ा म्युचुअल फण्ड "यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया" है।

मोर्टोरियम (Mortorium)

कानूनन ऋणों के भुगतान को टाल दिए जाने वाली अवधि को "Mortorium" या ऋण शोध स्थगन कहा जाता है।

मंदी (Recession)

मंदी (Recession) व्यापार चक्र की उस अवस्था को कहा जाता है जब देश में वस्तुओं की मांग घट जाती है। 1930 के दशक में विश्वव्यापी मंदी उत्पन्न हुई थी।

यूरो निर्गम (Euro Issue)

भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कतिपय प्रावधानों के अंतर्गत चुनिंदा भारतीय कंपनियों को विदेशी पूंजी बाजारों में निर्गम जारी करके विदेशी मुद्रा में पूंजी एकत्रित करने की छूट प्रदान कर दी है। इसी के अंतर्गत जब कोई भारतीय कंपनी विदेशों में अपना निर्गम जारी करती है तो यूरो निर्गम (Euro Issue) कहा जाता है।

यूजरी (Usury)

सूदखोरी को "यूजरी" (Usury) कहा जाता है।

यूटीलिटेरियनिज्म (Utilitarianism)

कल्याण हेतु सभी नियम एवं संस्थाओं का निर्माण "Utilitarianism" कहलाता है।

यूनीफाइड बजट :

भारत में राजस्व तथा पूंजीगत दोनों प्रकार के बजटों का मिलाकर प्रस्तुत करना।

राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)

किसी राज्य या संघीय सरकार के राजस्व घाटे, शुद्ध कर्ज की राशि, पूंजीगत प्राप्तियाँ तथा समग्र घाटे का योग राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) कहलाता है। एक अन्य परिभाषा के अंतर्गत राजस्व घाटे, पूंजीगत परिव्यय एवं शुद्ध उधार को राजकोषीय घाटा माना जाता है।

राजकोषीय कर्षण (Fiscal Drag)

इसका तात्पर्य यह है कि – वह बढ़ा हुआ भार जो कर की दरों में बिना किसी परिवर्तन किए हुए "मुद्रा स्फीति" के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो जाता है। राजकोषीय कर्षण (Fiscal Drag) की स्थिति में बढ़ी हुई मजदूरी एवं वेतन के कारण व्यक्ति ऊंचे कर स्लैब में पहुंच जाते हैं।

रिन्यूएबल रिसोर्सेज (Renewable Resources)

ऐसे संसाधन जो अनवरत् रूप से उपयोग में लाए जा सकते हैं, "पुनर्प्रयोज्य संसाधन" (Renewable Resources) कहते हैं। जैसे- सौर ताप या हवा ऐसे साधन हैं जिनसे अनवरत् रूप से ऊर्जा बनाई जा सकती है।

रिफ्लेक्शन (Reflation)

मंदी की अवस्था से उबरने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के फलस्वरूप लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है तथा मांगों में वृद्धि होती है तो मूल्य स्तर में भी वृद्धि होती है। इसे ही "Reflation" कहते हैं।

रिबेट (Rebate)

किसी संस्थान को दिए जाने वाले धन में छूट के रूप में एक निश्चित भाग कम कर दिया जाना "Rebate" कहलाता है।

राशिपतन (Dumping)

राशिपतन (Dumping) उस प्रक्रिया को कहते हैं जब किसी वस्तु के अति उत्पादन से बाजार में वस्तु के मूल्य को एक न्यूनतम स्तर से नीचे गिरने से बाजार में बहुत कम मूल्य पर बेचा जाता है अथवा नष्ट कर दिया जाता है।

राजस्व :

सरकार की करों द्वारा प्राप्त आय (प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों प्रकार के कर) राजस्व (Revenue) कहलाती है।

लिमिटेड कंपनी

लिमिटेड कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जिसमें हर शेयर होल्डर (धारक) का दायित्व अपने अंशदान तक ही सीमित होता है।

ले ऑफ (Lay off)

किसी औद्योगिक संस्थान में उत्पादन कम हो जाने या उस वस्तु की मांग कम हो जाने पर कर्मचारियों को नौकरी से पृथक करना "Lay off" कहलाता है।

लागत प्रेरित मुद्रा स्फीति (Cost Push Inflation)

जब वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप मूल्यों में वृद्धि होती है तथा मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी मुद्रा स्फीति को लागत प्रेरित कहा जाता है। श्रमिक संघों के दबाव में मजदूरी के स्तर में अनावश्यक वृद्धि से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है।

लदान बिल (Bill of Loading)

लदान बिल (Bill of Loading) अथवा लदान रसीद जहाज कंपनी द्वारा माल प्राप्ति की रसीद होती है।

उदारीकरण (Liberalization)

मुक्त बाजार की दिशा में अर्थव्यवस्था को ले जाने वाली नीति को "उदारीकरण" कहते हैं। इसमें अंतर्गत कर तथा मात्रात्मक प्रतिबंध को कम करना, मुद्रा को परिवर्तनशील बनाना, विदेशी पूंजी के देश में निवेश को प्रोत्साहन देना तथा देश के उद्योगों को यथासंभव बंधन मुक्त करने की नीतियां निहित होती हैं। परन्तु, उदारीकरण का यह अर्थ नहीं है कि अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में सरकार की भूमिका पूर्णतया समाप्त हो जाती है।

लाभांश (Dividend)

वह धन जो किसी कंपनी द्वारा अपने शेयर धारकों को उनके अंशदान के बदले में दिया जाता है, लाभांश (Dividend) कहलाता है।

लिबोर (London Inter-Bank Offer Rate, LIBOR)

लिबोर (London Inter-Bank Offer Rate, LIBOR) दर यूरोपीय करेंसी बाजार में प्रचलित है तथा इस पर किसी विशेष मुद्रा को उधार लिया जा सकता है।

वृद्धिमान पूंजी निर्गत अनुपात :

अर्थव्यवस्था में उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए पूंजी की जितनी अतिरिक्त इकाइयों की आवश्यकता होती है, उसे वृद्धिमानपूंजी निर्गत अनुपात (ICOR) कहते हैं। इसका अधिक होना यह दर्शाता है कि उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई की प्राप्ति हेतु ज्यादा पूंजी की आवश्यकता है।

विनिवेश (Disinvestment)

विनिवेश के अंतर्गत निम्नांकित प्रमुख बातें शामिल हैं –

1. किसी सार्वजनिक कंपनी के अंश, आंशिक या पूर्णरूप में किसी कंपनी को बेचना।
2. किसी निजी कंपनी की मशीनों को नष्ट करके उसकी पूंजी स्टॉक में कमी करना।
3. किसी निजी कंपनी द्वारा स्वयं की अपने कुछ अंश खरीद लेना।

परन्तु (प्रायः) इन तरीकों से देश में विद्यमान कुल पूंजी का स्टॉक कम नहीं होता। ज्ञातव्य है कि विनिवेश का उदारीकरण से कोई संबंध नहीं है।

विमुद्रीकरण (Demonetization)

जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है, तो इसे दूर करने के लिए "विमुद्रीकरण" (Demonetization) की विधि अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है तथा नई मुद्रा को जारी कर देती है।

विधिग्राह्य मुद्रा (Legal Tender Money)

ऐसी मुद्रा जिसमें भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है, उसे विधिग्राह्य मुद्रा (Legal Tender Money) कहते हैं।

विनिमय दर (Exchange Rate)

जिस दर पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित हो जाती है, उसे "विनिमय दर" (Exchange Rate) कहते हैं।

विवेकीकरण (Rationalization)

साधनों के आवंटन को और अधिक दक्षतापूर्ण बनाना, विवेकीकरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में, विवेक द्वारा उद्योगों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना विवेकीकरण है। यदि साधनों का उपयोग विवेकपूर्ण न हो तो उद्योगों का पुनर्गठन करके उसे अधिक दक्षतापूर्ण बनाना होता है। प्रायः इस प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत ऊंची लागत वाले प्लांटों को बंद करने से लेकर विभिन्न फर्मों में विलय तक के निर्णय लिए जा सकते हैं। इसी के अंतर्गत फर्मों में मौजूदा अधिकता को न्यूनतम करने के प्रयास आदि भी शामिल हैं।

विक्रेता बाजार (Sellers Market)

जब मांग अधिक होती है और पूर्ति कम, तब व्यापारी कमी का लाभ उठाकर वस्तुओं की मनमानी कीमतों पर बेचते हैं। ऐसे बाजार को विक्रेता बाजार (Sellers Market) कहते हैं।

विनिमय नियंत्रण (Exchange Control)

विनिमय नियंत्रण (Exchange Control) व्यवस्था के अंतर्गत कोई देश विदेशी मुद्राओं के स्वतंत्र बाजार पर नियंत्रण करके अपनी मुद्रा की विनिमय दर को उस दर से भिन्न रखने का प्रयास करता है, जो स्वतंत्र बाजार में निर्धारित होती है।

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता [Foreign Currency (Non-Resident) Account]

भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों को 1 नवम्बर, 1975 से उपर्युक्त प्रकार के खाते खोलने की अनुमति प्रदान की। इस प्रकार के खाते कुछ चुनी हुई परिवर्तनशील मुद्राओं में खोले जाते हैं। नकद जमाओं के अतिरिक्त विदेशों में निवासी भारतीय ड्राफ्ट, मेल ट्रांसफर, टेलीग्रॉफिक ट्रांसफर या चेक के द्वारा धनराशि भेज सकते हैं। जिस स्वीकृत मुद्रा में खाता रखा जाता है, ब्याज भी उसी मुद्रा में अदा किया जाता है तथा ब्याज पर भारतीय आयकर लागू नहीं होता।

वैश्विक गांव (Global Village)

मार्शल मकलुहान ने उस स्थिति को "वैश्विक गांव" (Global Village) की संज्ञा से अभिहित किया है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी के कारण दिन-प्रतिदिन दुनिया के लोग एक-दूसरे के निकट होते जा रहे हैं।

वेबलेन प्रभाव (Veblen Effect)

जब उपभोक्ता किसी वस्तु की गुणवत्ता उसकी कीमत के आधार पर निर्धारित करता है तो उसे "Veblen Effect" कहते हैं।

व्यापार शेष (Balance of Trade)

भुगतान संतुलन के चालू खाते का लेखा-जोखा व्यापार शेष (Balance of Trade) कहलाता है। इसके अंतर्गत चालू खाते के सिर्फ दृश्य व्यापार को ही शामिल किया जाता है।

विदेशी विनिमय भण्डार (Foreign Exchange Reserve)

किसी देश के पास उपलब्ध स्वर्ण और विदेशी मुद्राओं के भण्डार को विदेशी विनिमय भण्डार (Foreign Exchange Reserve) कहते हैं।

स्वीट शेयर (Sweet Shares)

स्वीट शेयरों (Sweet Shares) से तात्पर्य ऐसे शेयरों से है, जो कंपनी के कर्मचारियों या किसी अन्य को रियायती मूल्य पर आवंटित किए गए हों या फिर कोई प्रौद्योगिकी की अथवा बौद्धिक संपदा अधिकार कंपनी को उपलब्ध कराने या कोई अन्य मूल्य संवर्द्धन करने की एवज में निःशुल्क या रियायती मूल्य पर कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए हों। "सेबी" (SEBI) ने विशेष श्रेणी के स्वीट शेयरों के लिए 3 वर्ष का "लॉक इन पीरियड" (इन्हें किसी अन्य को इस अवधि में बेचा नहीं जा सकेगा) निर्धारित किया है।

संविभाग निवेश (Portfolio Investment)

वित्तीय विपत्रों में अंतर्राष्ट्रीय निवेश को संविभाग निवेश (Portfolio Investment) कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब एक देश के निवेशक दूसरे देश की कंपनियों के अंशों, ऋण पत्रों, बाण्डों तथा अन्य प्रतिभूतियों में धन लगाते हैं तो ऐसे निवेश को संविभाग निवेश कहा जाता है।

साख संकुचन (Credit Squeeze)

साख संकुचन (Credit Squeeze) का तात्पर्य है – कम मात्रा में ऋण वितरित करना। मुद्रा स्फीति की स्थिति रोकने के लिए केन्द्रीय बैंक द्वारा यह विधि अपनाई जाती है।

संयुक्त क्षेत्र (Joint Sector)

संयुक्त क्षेत्र (Joint Sector) में लगाए गए उद्योगों में सरकार व निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों का संयुक्त दायित्व होता है।

सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector)

सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) उसे कहते हैं, जिसके अंतर्गत संसाधन सरकार के स्वामित्व में होते हैं।

सार्वजनिक ऋण :

किसी देश में सरकार द्वारा लिया गया ऋण सार्वजनिक ऋण या "लोक ऋण" कहलाता है।

सॉफ्ट लोन (Soft Loan)

जिस ऋण को कम ब्याज और लम्बी अवधि जैसी आसान शर्तों पर प्राप्त किया जाता है, उसे "Soft Loan" कहते हैं।

स्टेगफ्लेशन (Stagflation)

स्टेगफ्लेशन (Stagflation) अर्थव्यवस्था की उस स्थिति को कहा जाता है, जिसमें मुद्रा स्फीति के साथ-साथ मंदी की स्थिति भी होती है।

सेमी बोम्बला (Semi Bombla)

किसी देश के अर्थशास्त्रियों द्वारा तैयार किया गया प्रपत्र, जिसके द्वारा कालाधन, मुद्रा प्रसार, कीमत वृद्धि आदि आर्थिक समस्याओं को सुलझाने हेतु सुझाव होते हैं, “Semi Bombla” कहलाता है।

शुद्ध पुनरुत्पादन दर या शुद्ध प्रजनन दर (Net Reproduction Rate)

इसे कुजिंस्की की प्रजनन दर भी कहा जाता है। “शुद्ध प्रजनन दर” (Net Reproduction Rate) वह दर है जिस पर किसी देश की महिला जनसंख्या अपने आपको प्रतिस्थापित करती है। यदि $NRR=1$ हो तो देश की जनसंख्या में स्थिरता की प्रवृत्ति होगी। यह दर 1 से अधिक होने पर जनसंख्या में वृद्धि होती है तथा 1 से कम होने पर जनसंख्या घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है।

स्पेशल ड्राइंग राइट्स (Special Drawing Rights, SDR)

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की मौद्रिक सम्पत्ति जो उनके अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व का हिस्सा है, एसडीआर कहलाता है। दिसंबर, 1971 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) के समस्त लेन-देन “विशेष आहरण अधिकार” (SDR) के रूप में व्यक्त किए जाने लगे। 1 जनवरी, 1981 से SDR का मूल्य 5 सबसे बड़े निर्यातक देशों (U.S.Dollar, Mark, Yen, Franc & Pound Sterling) की “बास्केट” के आधार पर निर्धारित किया जाने लगा। 1987 में 6 बिलियन SDR या 8 बिलियन डॉलर का एक कोष (The Enhanced Structural Adjustment Facility, ESAF) बनाया गया।

सस्ती मुद्रा (Cheap Money)

वह मुद्रा जिसे नीची ब्याज दर पर प्राप्त किया जा सकता है, सस्ती मुद्रा (Cheap Money) कहलाती है।

समपार्श्विक प्रतिभूति (Collateral Security)

समपार्श्विक प्रतिभूति (Collateral Security) ऋण की सुरक्षा के दृष्टिगत प्राथमिक प्रतिभूति के अतिरिक्त ऋणी से प्राप्त की जाती है।

सरकारी प्रतिभूति (Government Securityes)

सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securityes) में सरकारी प्रतिज्ञा पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र तथा राष्ट्रीय बचत योजना व वाहक बंधक पत्र आदि शामिल हैं।

स्मार्टकार्ड :

डाक विभाग द्वारा जारी "स्मार्ट कार्ड" के माध्यम से खातेदार विभिन्न डाकघरों में अपने खाते में धन जमा कर सकते हैं।

सीमांत उत्पादकता व उपयोगिता (Marginal Productivity and Utility)

जब उत्पादन के किसी साधन की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से संपूर्ण उत्पादन में वृद्धि होती है तो उसे सीमांत उत्पादकता (Marginal Productivity) कहते हैं। दूसरी ओर, जब किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से संपूर्ण उपयोगिता में वृद्धि होती है तो उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं।

स्वर्णमान (Gold Standard)

स्वर्ण में परिवर्तनशील हो सकने वाली किसी देश की प्रधान मुद्रा जिसका मूल्य सोने में मापा जाता है "स्वर्ण मान" (Gold Standard) कहलाता है।

सूचकांक (Index Number)

किसी वस्तु के मूल्य में किसी आधार वर्ष या किसी अवधि की तुलना में हुए प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाने वाले अंक को सूचकांक (Index Number) कहते हैं।

हालमार्क

इसका संबंध स्वर्णाभूषणों की गुणवत्ता को मापना है।

हार्ड करेंसी (Hard Currency)

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की पूर्ति की तुलना में लगातार मांग अधिक होती है। वह हार्ड करेंसी (hard Currency) कहलाती (प्रायः विकसित देशों की मुद्रा) है।

हीनार्थ प्रबंध (Deficit Financing)

जब सरकार का बजट घाटे का होता है अर्थात् आय कम होती है किन्तु व्यय अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में व्यय के आधिक्य को सरकार केन्द्रीय बैंक से ऋण लेकर तथा पत्र मुद्रा निर्गमन आदि का सहारा लेकर पूर्ण करती है। इस व्यवस्था को "घाटे की वित्त व्यवस्था" या हीनार्थ प्रबंधन कहा जाता है।

हॉट मनी (Hot Money)

वह विदेशी मुद्रा "Hot Money" कहलाती है, जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है तथा जिस स्थान पर अधिक लाभ मिलने की संभावना होती है, वह वहीं स्थानांतरित हो जाती है।

हायर परचेज (Hire Purchase)

जब कोई वस्तु मासिक या वार्षिक किश्त के आधार पर खरीदी जाती है तो इस विधि को "Hire Purchase" कहा जाता है।